

भारतीय संघ

बनाम

मैसर्स चतुर्भाई एम. पटेल एंड कंपनी

और विपरीत क्रम से

9 दिसम्बर, 1975

[के.के. मैथ्यू और एस. मुर्तजा फज़ल अली, जे.जे.]

*धोखाधड़ी- को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए- मात्र
संदेह- यदि धोखाधड़ी का सबूत है।*

प्रतिवादी ने भारत संघ के विरुद्ध यह आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया कि रेलवे की लापरवाही के कारण उसके द्वारा गया भेजी गई तम्बाकू की खेप पारगमन में प्रतिस्थापित हो गई और उसके स्थान पर गया में निम्नतर तम्बाकू की डिलीवरी की गई। दूसरी ओर, रेलवे ने प्रतिवादी और उसके पिता, जो कि गुजरात में एक बीड़ी तम्बाकू व्यापारी हैं, के बीच धोखाधड़ी और मिलीभगत का आरोप लगाया, क्योंकि जानबूझकर हेरफेर करके, प्रतिवादी ने गया को घटिया माल और गुजरात को बेहतर माल भेजा।

विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी के वाद को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रतिवादी द्वारा भुगतान की गई उत्पाद शुल्क को वापस करने से इनकार कर दिया।

इस न्यायालय में अपील को खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया:

(1) अपीलकर्ता धोखाधड़ी का मामला स्पष्ट नहीं कर पाया था। धोखाधड़ी की दलील को नकारने और वाद पर फैसला सुनाने में उच्च न्यायालय उचित था। [904-एफ]

(2) धोखाधड़ी, आपराधिक अपराध के किसी भी अन्य आरोप की तरह, चाहे वह सिविल या आपराधिक कार्यवाही में की गई हो, को उचित संदेह से परे साबित करना चाहिए। परिस्थितियाँ कितनी भी संदेहास्पद क्यों न हों, संयोग कितने भी अजीब क्यों न हों और संदेह कितने भी गंभीर क्यों न हों, मात्र संदेह कभी भी प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता। [904-एफजी]

ए.एल.एन. नारायणन चेट्टियार बनाम आधिकारिक समनुदेशिती,
उच्च

कोर्ट रंगून, एआईआर 1941 पीसी 93, संदर्भित।

इस मामले में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि खेप को गुजरात या गया भेजे जाने से पहले प्रतिवादी और उसके पिता के बीच पहले से कोई सहमति नहीं थी, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि इन दोनों व्यक्तियों ने अपीलकर्ता को धोखा देने के लिए एक साजिश रची थी। [904-ईएफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 972-973/1968।

प्रथम अपील संख्या 285/1958 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और डिक्री दिनांक 1 दिसंबर 1961 से।

अपील 972 में अपीलकर्ताओं के लिए और सीए 973/68 में प्रतिवादियों के लिए गोबिंद दास और एसपी नायर।

अपील 972 में प्रतिवादी के लिए एसएम जैन, जेपी गोयल, एसके जैन और श्रीपाल सिंह और सीए 973/68 में अपीलकर्ता के लिए।

न्यायालय का फैसला फ़ज़ल अली, जे. द्वारा सुनाया गया। प्रतिवादी की यह अपील प्रमाण पत्र द्वारा है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 133(1) के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया है। वादी, जो बनारस में बीड़ी तम्बाकू का कारोबार करने वाली एक पंजीकृत साझेदारी फर्म है, ने इस आरोप पर प्रतिवादी भारत संघ के खिलाफ

क्षतिपूर्ति के लिए वर्तमान मुकदमा दायर किया कि इसने बनारस में तम्बाकू की एक खेप बिहार के गया के लिए चतुरभाई एम पटेल एंड कंपनी को गया में डिलीवरी के लिए भेजी थी। यह माल इनवॉइस नंबर 107 रेलवे रसीद नंबर 89551 दिनांक 9 जुलाई 1954 के तहत बुक किया गया था। वादी का आरोप था कि रेलवे की लापरवाही के कारण वादी द्वारा भेजा गया समान माल गया में परेषिती तक नहीं पहुंचा, लेकिन निम्न प्रकार का तम्बाकू वहाँ पहुँच गया जिससे वादी को गम्भीर हानि हुई। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत नोटिस देने के बाद मुकदमा दायर किया गया था। वादी ने उस उत्पाद शुल्क को लौटाने का भी दावा किया जो वादी द्वारा भुगतान किया गया था। मुकदमे का प्रतिवादी ने मुख्य रूप से इस आधार पर विरोध किया था कि बनारस में वादी और गुजरात में उसके पिता की फर्म के बीच धोखाधड़ी और मिलीभगत के कारण, हेरफेर और विचार-विमर्श द्वारा बनारस में माल की अदला-बदली की गई थी ताकि घटिया माल गया भेजा गया और बेहतर माल गुजरात भेजा गया, जिसे फर्म द्वारा गुजरात में बेचा जाता था और उपरोक्त फर्म द्वारा भारी मुनाफा कमाया जाता था।

विचारण न्यायालय ने कई विवाद्यक विरचित किए और बचाव पक्ष के तर्कों को स्वीकार किया और तदनुसार मुकदमे को खारिज कर दिया। इसके बाद वादी ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक अपील दायर की, जिसने विचारण न्यायालय के फैसले और डिक्री को पलट दिया और वादी के

हर्जाने के मुकदमे का फैसला सुनाया, लेकिन वादी द्वारा भुगतान की गई उत्पाद शुल्क की राशि के संबंध में डिक्री पारित करने से इनकार कर दिया।

अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए श्री गोबिंद दास ने कहा कि ऐसी कई संदिग्ध परिस्थितियां हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि वादी और उसके पिता की गुजरात में मिलीभगत से, जिनकी कंपनी मंगल भाई प्रभु दास के नाम से जानी जाती थी, प्रतिवादी के साथ कुछ धोखाधड़ी की गई थी। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने तीन या चार परिस्थितियों पर भरोसा किया है जिन पर उच्च न्यायालय ने उचित रूप से विचार किया है।

उच्च न्यायालय के फैसले का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि मामला तथ्यात्मक निष्कर्षों के आधार पर समाप्त हुआ है और आम तौर पर अपीलकर्ता को अपील करने की अनुमति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता था, लेकिन इस तथ्य के लिए कि उच्च न्यायालय का निर्णय पहले दिये गए निर्णय को बदलने के संबंध में था और मुकदमे का मूल्यांकन 20,000/- रुपये से अधिक था। फिर भी उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी/अपीलकर्ता द्वारा भरोसा की गई संदिग्ध परिस्थितियों पर चर्चा की है और माना है कि धोखाधड़ी या मिलीभगत को साबित करने के लिए कोई निर्णायक या विश्वसनीय सबूत नहीं था जैसा कि प्रतिवादी ने आरोप लगाया था। परिस्थितियों में से एक यह थी कि 9 जून 1954 को वादी के पिता

मंगई भाई प्रभु दास द्वारा गुजरात के रेलवे स्टेशन वसाड से इंडियन ज़राडा फैक्ट्री, बनारस के लिए 191 बैग तम्बाकू की एक खेप बुक की गई थी, जिसका स्वामित्व वादी के पास था। इस खेप की डिलीवरी बनारस में इंडियन ज़राडा फैक्ट्री के एक एजेंट मोहनलाल द्वारा की गई थी और इसे बनारस में फैक्ट्री के बंधुआ गोदाम में फिर से रखा गया था। उसी दिन वादी का माल भी उसी स्थान पर गोदाम में रख दिया गया। इसके बाद 24 जून 1954 को इंडियन ज़राडा फैक्ट्री की ओर से बनारस में उनके पिता मंगल भाई प्रभु दास पटेल को गुजरात में 174 बैग तम्बाकू भेजने के लिए एक अग्रेषण नोट इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि माल निम्न गुणवत्ता का था। बताया जाता है कि घटिया क्वालिटी का माल जानबूझ कर गया भेजा गया, जबकि दूसरा माल बैग पर मार्क बदल कर गुजरात भेज दिया गया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने बताया है कि यह दिखाने के लिए कोई भी सबूत नहीं है कि इस तरह की हेराफेरी या चिन्हों का बदलाव वादी या उसके एजेंट द्वारा बनारस में किया गया था।

इसी तरह इस तथ्य पर भी भरोसा किया गया कि यद्यपि खेप 17 जुलाई, 1954 को गया पहुंची थी, फिर भी उपरोक्त खेप की डिलीवरी वादी के चचेरे भाई द्वारा एक महीने से अधिक समय बाद यानी 25 अगस्त, 1954 को गया में ली गई थी और वह भी गया के रेलवे के अधिकारियों द्वारा 23 अगस्त, 1954 को परेषिति को एक पत्र भेजे जाने के बाद। उच्च

न्यायालय ने बताया है कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि गया में माल भेजने वाले को पता था कि माल 17 जुलाई, 1954 को वहां आया था और गया में वादी के चाचा को जो पत्र भेजा गया था वह बहुत दिनों के बाद उन्हें प्राप्त हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रेलवे अधिकारियों की ओर से कुछ हद तक लापरवाही हुई है क्योंकि उन्होंने माल प्राप्त होने के एक महीने से अधिक समय बाद गया में परेषिती को एक पत्र लिखा था और और यदि यह पत्र उन्होंने खेप प्राप्त होने के तुरंत बाद भेजा होता, और यदि इसके बावजूद डिलीवरी लेने में देरी हुई होती तो वादी के पक्ष में कुछ कहा जा सकता था।

अंत में अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री गोबिंद दास द्वारा यह आग्रह किया गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वादी, जो बनारस में इंडियन ज़राडा फैक्ट्री का मालिक था और उसके पिता, जो गुजरात में फर्म के मालिक थे, ने अपने करीबी रिश्ते को देखते हुए प्रतिवादी को धोखा देने की साजिश रची है। उच्च न्यायालय ने ठीक ही बताया है कि वादी एक विलग बेटा है और उसका अपने पिता के साथ तंबाकू के व्यवसाय को छोड़कर कोई भी सामान्य संबंध नहीं है, जो दो अलग-अलग स्थानों पर किया जाता है। उच्च न्यायालय ने यह भी बताया कि पिता ने दूसरी शादी की है और इससे पता चलता है कि वादी और उसके पिता के बीच कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है। इसके अलावा, इस बात का

कोई सबूत नहीं है कि खेप को गुजरात या गया भेजे जाने से पहले वादी और उसके पिता के बीच कोई पूर्व बैठक हुई थी, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि इन दोनों व्यक्तियों ने प्रतिवादी के साथ धोखाधड़ी करने के लिए एक साजिश रची थी। इसलिए, इस तर्क में कोई बल नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा भरोसा की गई विभिन्न परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिनिर्धारित किया है कि वे धोखाधड़ी के मामले को साबित करने के लिए बिल्कुल भी निर्णायक नहीं हैं। यह सुस्थापित है कि आपराधिक अपराध के किसी भी अन्य आरोप की तरह धोखाधड़ी, चाहे वह सिविल या आपराधिक कार्यवाही में लगाई गई हो, उचित संदेह से परे साबित की जानी चाहिए; लॉर्ड एटकिन के अनुसार ए.एल.एन. नारायणन चेट्टियार बनाम आधिकारिक समनुदेशिती, उच्च न्यायालय रंगून में (ए.आई.आर. 1941 पी.सी. 93)। परिस्थितियाँ कितनी भी संदेहास्पद क्यों न हों, संयोग कितने भी अजीब क्यों न हों, और संदेह कितने भी गंभीर क्यों न हों, मात्र संदेह कभी भी प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता। हमारे सामान्य जीवन में हमें कभी-कभी अस्पष्ट घटनाओं और अजीब संयोगों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि, जैसा कि कहा जाता है, सच्चाई कल्पना से अधिक मजबूत होती है। इन परिस्थितियों में, इसलिए, उच्च न्यायालय के फैसले को पढ़ने के बाद हम

संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ता उच्च न्यायालय द्वारा पाए गए धोखाधड़ी का मामला बनाने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार धोखाधड़ी की दलील को अस्वीकार करने और वादी के मुकदमे पर फैसला सुनाने में उच्च न्यायालय पूरी तरह से न्यायोचित था।

वादी द्वारा भुगतान की गई उत्पाद शुल्क की राशि को अस्वीकार करने के लिए वादी/प्रतिवादी द्वारा प्रति-आपत्तियां दायर की गई हैं। उच्च न्यायालय के फैसले का अवलोकन करने के बाद, हम इन प्रति-आपत्तियों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

इसका परिणाम यह है कि अपील और प्रति आपत्तियां खारिज कर दी जाती हैं, लेकिन मामले की परिस्थितियों में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

पीबीआर

अपील खारिज की जाती हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक खुशबू सोनी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।